प्रावधान - प्रतिक्रियाएं

मेट्रो रेल के काम पर 656 करोड़ खर्च करेगी सरकार

भोपाल. राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के विस्तार कार्यक्रम पर 656 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इन दोनों ही शहरों में पहले चरण का काम हो गया है, अब दूसरे चरण का काम चल रहा है. इस चरण का काम भी वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. नगरीय विकास एवं विकास विभाग के तहत सिंहस्थ से जुड़े कार्यों के लिए 3060 करोड़ रुपए तो मिलियन प्लस शहर अमृत 2.0 के लिए 1418 करोड़, निकायों में मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान के तहत 1058 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी. कायाकल्प अभियान के लिए 200 करोड़, गीता भवनों के निर्माण के लिए 60 करोड़ और अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड के लिए भी 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सीएम वृंदावन ग्राम योजना के लिए 104 करोड़ मिलेंगे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत सीएम वृंदावन ग्राम योजना के लिए 104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार करोड़, पीएम सड़क योजना की सड़कों के मरम्मत और उन्नयन पर 1285 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण 900 करोड़ में किया जाएगा. पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोइयों को मानदेय के लिए 640 करोड़ पीएम जनमन सड़क योजना के लिए 603, ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 603 और सीएम आवास मिशन के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बजट में सामाजिक न्याय विभाग के लिए 2343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पर 1152 करोड़, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पर 400 करोड़ रुपए, सीएम कन्या विवाह पर 262 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

सुरेश राजे विधायक डबरा

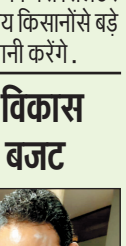

कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे ने बताया कि इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है. सिर्फ खोखले आंकड़े हैं. सरकार कहती है कि हमने कोई भी नया टेक्स नहीं लगाया है लेकिन यह बताये कि नौजवानों को क्या दिया किसानों और व्यापारियों को क्या दिया. चौहत्तर हजार करोड़ के घाटे का बजट है. सरकार प्रदेश को कर्ज के दल दल में फसा चुकी है.सरकार ने जो कर्ज ले रखा उसकी भरपाई कर रही है. इस बजट से जनता को निराशा हाथ लगी है इस लिए हम इस बजट का विरोध करते हैं.

अनुभा मुंजारे की प्रतिक्रिया

कांग्रेस की बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट जो पेश किया गया है यह सिर्फ लोक लुभावना है हकीकत से कोई लेना देना नहीं है. सपना दिखाने वाला है.अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी महिलाओं को रोजगार दिया है या उनके लिए लघु उद्योग खोलने के लिए कितने प्रयास किए गए. सरकार मंहगाई पर रोक लगाने में असफल रही है महिलाओं का संबंध किचिन से अधिक होता है तो रसोई गैस राशन सहित अन्य सामान महंगे हुए हैं .गैस सिलेंडर चार सौ रुपए से ग्यारह सौ रुपए में मिल रहा है. उज्जवला योजना ठप पड़ी है लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. इन्होंने चुनाव के समय किसानोंसे बड़े बड़े वादे किया थे किसानों की आए दुगनी करेंगे.

हकीकत से दूर और विकास विरोधी है प्रदेश का बजट

प्रदेश सरकार प्रस्तुत बजट पर विधायक सचिन यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों के पूरी तरह विपरीत और विकास विरोधी है. सरकार केवल खोखले दावों और आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए जनता को गुमराह कर रही है. प्रदेश आज बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन बजट में कोई समाधान या ठोस रोडमैप नहीं है. सचिन यादव ने कहा कि सरकार पर लगभग .4,000 करोड़ रुपये घाटे का बजट है. यह बजट आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और कमजोर करेगा. सरकार ने अमेरिका से व्यापार समझौता कर देश के किसानों की कब्र खोदी है. प्रदेश और देश के किसानों के हितों के खिलाफ है. पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए किया गया बजट आवंटन 'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित हो रहा है.

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पाण्डे की बजट पर प्रतिक्रिया

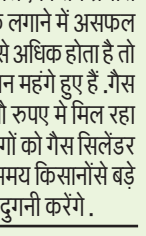

विधानसभा में प्रस्तुत बजट को मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पाण्डेय ने खोखले वादों का बजट निरूपित किया है. यह बजट प्रदेश की आम जनता के साथ छलावा है और कर्मचारी मजदूर विरोधी है. सरकार ने चार लाख अड़तीस हजार तीन करोड रुपए का बजट प्रस्तुत किया है. वहीं 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक का घाटे का बजट भी बताया है तो फिर घोषित योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? यह बजट सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन बजट में इस पर कोई स्पष्ट नीति, योजना या समयसीमा नहीं है. पाण्डेय नेकहा कि बजट में युवाओं की नौकरी और भर्ती पर चुप्पी है. प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी कि भर्ती, नई नौकरियों और रोजगार सृजन पर ठोस प्रावधान होंगे.

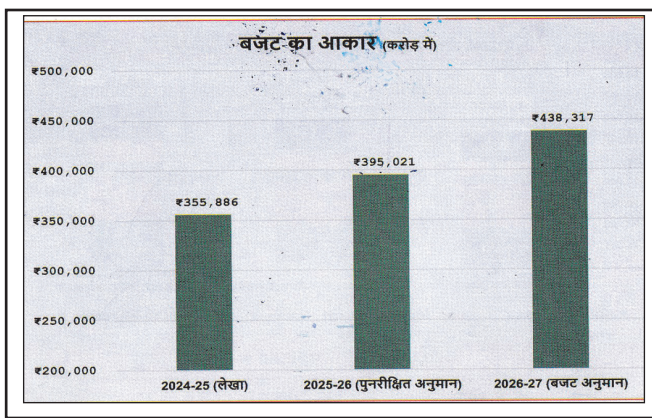

जेट विमान, हेलीकॉप्टर खरीदेगी सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 फरवरी. राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में नया जेट विमान और हेलीकॉप्टर भी खरीदेगी. अभी सरकार को वीआईपी के मूवमेंट के लिए किराए पर जेट लेना पड़ता है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद राज्य सरकार इस मामले में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है. इसलिए ही बजट में नया जेट खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 180 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है.

बजट में ये भी खास

- पीएम कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत 3 हजार करोड़ की लागत के एक लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे.
- कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा के लिए उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ में सखी-निवास का निर्माण.
- मुख्यमंत्री मजरा- टोला सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के जिलए 800 करोड़ का इंतजाम.
- एक हजार 766 पुल और पुलियों के निर्माण की 4 हजार 572 करोड़ की क्षतिग्रस्त पुलों का पुर्ननिर्माण योजना मंजूर. नए बजट में 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- सिंहस्थ महापर्व के कामों के लिए 3 हजार 60 करोड़ का इंतजाम.

विधायकों का स्वेच्छा अनुदान भी नहीं बढ़ेगा

बजट में विधायकों के स्वेच्छा अनुदान मद में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं हुई है.

विधायकों के लिए इस मद में 173 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं विधायकों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि भी यथावत रखी गई है. इस मद में फिलहाल 575 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है.

मतदाता सूची तैयार करने 132 करोड़ रुपए खर्च होंगे

मतदाता सूची तैयार करने और मुद्रण कराने के लिए बजट में 132 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है. वहीं न्यायालय भवनों के निर्माण पर 301 करोड़ रुपए, उच्च न्यायालय भवन और आवासीय परिसरों के निर्माण पर 105 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ग्राम न्यायालय के लिए भी 87 करोड़ रुपए मिलेंगे.

आपदा प्रबंधन के लिए 1449 करोड़ का प्रावधान

राजस्व विभाग के तहत आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए 1449 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं तहसील, जिला और संभाग के भवन और आवासीय परिसरों के निर्माण पर 411 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ओला पीड़ितों को राहत के लिए बजट में 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना होगी

गृह विभाग के तहत राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना होगी, इस पर 129 करोड़ रुपए खर्च होंगे. अपराध अनुसंधान विभाग के तहत 429 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. गृह विभाग के सामान्य व्यय जिला पुलिस के लिए 7250 करोड़ और सामान्य व्यय विशेष पुलिस के लिए 2352 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है.

सीएम स्वेच्छानुदान के लिए 200 करोड़

बजट में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के लिए 78 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है. मंत्रालय के लिए भी 270 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ये राशि मंत्रालय के रिनोवेशन पर खर्च होगी.

बजट में मप्र के संपूर्ण विकास के प्रावधान

भोपाल. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है. इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी.

श्री राजपूत ने कहा कि इस बजट में मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण, युवा शक्ति,अन्नदाता, नारी शक्ति, अधोसंरचना और उद्योग पर फोकस किया है. इस बजट से प्रदेश के कृषि विकास औद्योगिक निवेश, अधोसंरचना विकास के संतुलित संयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने कि दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गो के कल्याण के लिये समुचित प्रावधान किये है. खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि नये बजट में अंत्योदय की अवधारणा को साकार करने के लिये गरीब कल्याण की दिशा में सरकार ने अल्प आय तथा समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुये वर्ग के कल्याण के लिये ' 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान'' के तहत 793 करोड़ का प्रावधान किया है. सरदार पटेल कोचिंग योजना के तहत 4000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है.

म्युचुअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

एन बी सी सी NBCC A Navratna CPSE
माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली आवास परियोजना लर्नेड कोर्ट रिसीवर के माध्यम से एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा निष्पादित
ASPIRE
ई-नीलामी के माध्यम से मालसूची की थोक बिक्री

एस्पायर सिलिकॉन सिटी
फेज़-IV, सेक्टर-76, नोएडा, उत्तर प्रदेश
- मालसूची आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4 बी.एच. के. और विशाल डुप्लेक्स अपार्टमेंट
- स्पेक्ट्रम मॉल, नोएडा के पास और निकटतम मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर-50 (एक्वा लाइन) एवं सेक्टर-76 मेट्रो हैं तथा आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 25 मिनट

एस्पायर सिलिकॉन सिटी

एस्पायर लेज़र पार्क

एस्पायर लेज़र पार्क
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
- मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी.एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
- डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 30 मिनट

एस्पायर लेज़र वैली
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
- मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच. के. एवं 4 बी. एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
- डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 35 मिनट

एस्पायर लेज़र वैली

एस्पायर सेंचुरियन पार्क

एस्पायर सेंचुरियन पार्क
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
- मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच. के. एवं 4 बी. एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
- डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 30 मिनट

ई.एम.डी. जमा करने की अंतिम तिथि: 27.02.2026
ई-नीलामी 28.02.2026 को आयोजित की जाएगी
ई.एम.डी. राशि 9.70 करोड़ रु. से 20.90 करोड़ रु. तक
6 पैकेज जिनका मूल्य 485 करोड़ रु. से 1,045 करोड़ रु. तक है
प्री-बिड मीटिंग दिनांक 19-02-2026 को सुबह 11:30 बजे डबल्यू टी सी, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी
कृपया ई-नीलामी दस्तावेज के लिए क्यू आर स्कैन करें:
कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें: www.nbccindia.in | www.receiveramrapali.in
या : 9772907414